रणनीति की दिशा

गरीबी दूर करने की चुनौती और शताब्दिक विकास ध्येय (मिलेनियम डेवलपमेन्ट गोल्स) को प्राप्त करना बहुत बड़ा काम है।

पिछले दो दशकों से गरीबी घटाने के बहुत से प्रयत्नों के बाद भी - पिछले दो दशकों में **200** मिलियन लोग गरीबी से बाहर आए - **1.2** बिलियन लोग आज भी प्रतिदिन **$1** से भी कम पर जीते हैं। जबकि **2.8** बिलियन लोग आज भी प्रतिदिन **$2** से भी कम पर जीते हैं। आगामी **50** वर्षों में विश्व की जनसंख्या छ: से नौ बिलियन होना अनुमानित की गयी है, जिसकी लगभग **95** प्रतिशत वृद्धि विकासशील देशों में होगी।

ध्येय

शताब्दिक विकास ध्येय (मिलेनियम डेवलपमेन्ट गोल या एम डी जी), सन् **2002** में संयुक्त राष्ट्र की शताब्दिक संगोष्ठी में, **189** देशों ने गरीबी उन्मूलन के सतत् प्रयास के लिये क्या आवश्यक है इस विषय पर अप्रत्याशित स्तर की आम सहमति जताई। ध्येय में विशिष्ट लक्ष्य रखे गए हैं और जिसके लिये पूरा विकास समुदाय - सभी दानदाता और दान प्राप्तकर्ता - समान रूप से कार्य करेंगे।

1. अति गरीबी और भुखमरी का सफाया करें
2. सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं
3. स्त्री-पुरुष समानता एवं स्त्रियों को अधिकार देने को बढ़ावा दें
4. बच्चों की मृत्यु दर में कमी लायें
5. एचआईवी/एड्स, मलेरिया, और अन्य बीमारियों का मुकाबला करें
6. पर्यावरणीय बेहतरी को बनाये रखें
7. विकास के लिये वैश्विक साझेदारी विकसित करें

अभी तक, ऐसा लगता है कि प्रथम ध्येय - सन् 1990 से 2015 तक अति गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या का अनुपात आधा करना एवं पीने के लिये साफ पानी की प्राप्ति में सुधार - पूरा हो जायेगा। परन्तु यह आंकड़े वैश्विक औसत दर्शाते हैं, जबकि वास्तविक परिणाम सम्पूर्ण विश्व में असमान होंगे, विशेष तौर पर अफ़्रीका में ये कम रहेंगे।
अन्य बातों के अतिरिक्त, अन्तिम लक्ष्य दानदाताओं और दानप्राप्त कर्ताओं की भूमिका पर प्रकाश डालता है। ताज़े विश्व सम्मेलनों - जिनमें सन् **2002** के मोन्टेरी में विकास के लिये वित्तीय व्यवस्था का सम्मेलन और सतत् गतिमान विकास पर, जोहानॅसबर्ग में विश्व शिखर सम्मेलन ने एक नयी धारणा उत्पन्न होते देखी, जहाँ विकसित देशों ने व्यापार में रुकावटों को कम किये जाने, सहायता बढ़ाने और ऋण के बोझ को कम किये जाने की आवश्यकता को महसूस किया। एम डी जी की प्राप्ति के लिये कई विकासशील देशों द्वारा सही आर्थिक नीतियों, भ्रष्टाचार मुक्त और असरदार सरकारी क्षेत्रों का प्रबन्धन, तथा ऐसा वातावरण जो निजी क्षेत्र को भी पोषित करे, बनाने की आवश्यकता है।

विश्व बैंक की भूमिका क्या है ?

विश्व बैंक ऋण देने, गारन्टी देने, विश्लेषण और सलाह देने के कार्य, ऋण मुक्ति, क्षमता वृद्धि, और वैश्विक परिवेक्षण और उचित अनुशंसाओं हेतु विकसित और अविकसित दोनों ही प्रकार के देशों को सहयोग करता है।

- **विश्व बैंक की गरीबी उन्मूलन की रणनीति, निवेश के लिये वातावरण बनाने और गरीब लोगों में निवेश करने पर आधारित है।**

सन् **2001** के योजनागत कार्य के दस्तावेज़ (स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क पेपर) में, बैंक द्वारा दो आधार स्तम्भों की पहचान की गयी जिन पर बैंक ऋण देने, सलाह देने के कार्य , और क्षमता वृद्धि के अपने क्रिया कलापों पर ध्यान केन्द्रित करेगी ताकि, एम डी जी के : निवेश के लिये वातावरण बनाने, नौकरियों, और सतत् गतिमान वृद्धि, तथा गरीब लोगों में निवेश व उन्हें विकास कार्यो में हिस्सेदार बनने के लिये अधिकार देना, आदि की प्राप्ति हो।
प्रथम आधार स्तम्भ इस सबूत पर आधारित है कि सबसे अधिक सफल विकास वह है जो कि निजी क्षेत्र द्वारा प्रवंधित है, परन्तु वह ऐसी सरकार द्वारा सुविधा प्रदत्त हो जो कि उद्यमी वृत्ति पनपने दे, आर्थिक क्रिया कलापों के लिये उपयुक्त वातावरण बनने दे, मूलभूत सुविधायें, मानव पूँजी, और एक उपयुक्त कानूनी व न्यायिक प्रणाली उपलब्ध कराये।
दूसरा आधार स्तम्भ, यदि गरीब लोगों को आर्थिक अवसर पाने के लिए तैयार करना है तो स्वास्थ्य और शिक्षा का महत्व बढ़े तथा आपदाओं के समय कम से कम नुकसान हो इस बात को प्रतिबिम्बित करे।

सात प्रमुख क्षेत्र : सन् 2003 के आरम्भ में, बैंक के प्रबन्धन ने विशेष ध्यान हेतु सात क्षेत्रों को तय किया : सभी को शिक्षा, एच आई वी/एड्स से मुक्ति, माँ-बच्चे का स्वास्थ्य, पानी की आपूर्ति और सफाई, निवेश के लिये वातावरण, वित्तीय व्यवस्था, व्यापार, और पर्यावरणीय बेहतरी।
बैंक द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले सभी क्षेत्रों में से इन क्षेत्रों को अति महत्वपूर्ण माना गया है, इनमें बैंक आने वाली अवधि में प्रभाव बढ़ायेगा। इसका अर्थ होगा क्षमता अधिक बढ़ाने की योजना बनाना, प्रक्रिया को तेज करना, साथ ही परम्परागत वित्तीय सुविधा और पूँजी भी प्रदान करना। 1944 में जब इन्टरनेशनल बैंक ऑफ रिकन्सट्रक्शन एन्ड डेवेलपमन्ट की नींव रखी गयी, तब "विकास" केंद्र में नहीं था, यह बाद में सोचा विचार है। उस समय विश्व बैंक का मुख्य कार्य युद्ध के बाद यूरोप का पुन: निर्माण करना था।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अमीर देशों का यह सिद्धान्त चलन में आया कि गरीब देशों में जीने के स्तर को सुधारा जाए। तबसे कई दशकों में, गरीबी हटाने और आर्थिक समृद्धि के बीच के आपसी रिश्ते अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की समझ में आये जिसके फलस्वरूप सरकारी-निजी भागीदारी, भाग लेना, अधिकार देना और शासन प्रणाली का विकास हुआ।

- **मूलभूत रूप से, यह तो साफ है कि केवल आर्थिक प्रगति ही निश्चित रूप गरीबी को कम नहीं करती।**

सन् 2000, में विश्व बैंक ने गरीबी पर एक पथ प्रदर्शक अध्ययन छापा। गरीबों की आवाज़, ने स्वयं गरीबों तक पहुँच कर विश्व की गरीबी के कारणों और उसके प्रभावों का अनावरण किया : 60 देशों के 60,000 पुरूषों और स्त्रियों ने अपनी गरीबी की असलियत का विस्तृत विवरण दिया, और बताया कि एक गरीब को अपने जीवन को सुधारने के लिये क्या चाहिये। अध्ययन ने दर्शाया कि गरीबी मौलिक रूप से किस स्तर तक मानव विकास के अन्य हिस्सों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सरकार में हिस्सेदारी आदि से किस प्रकार आपस में जुड़ी है, और किस सीमा तक भ्रष्टाचार और बेअसर सरकारी कार्यक्रम अपनी भूमिका अदा करते हैं।
बैंक द्वारा "गरीबी पर शिकंजा" पर सन् 2000/2001 विश्व विकास की रिपोर्ट को बल देने के लिये *आवाज़* पर अनुसंधान किया गया, इसने विश्व बैंक द्वारा अपने कार्यों को संचालित करने के ढंग से सम्बन्धित अभी हाल के कई परिवर्तनों को प्रभावित किया है। गरीबी पर शिकंजा कसने के लिये रिपोर्ट में नयी रूप रेखा दी गयी है।

- सुअवसरों को बढ़ाना, यानि तर्कसंगत आर्थिक उन्नति में हाथ बंटाना, बाजार तक पहुँच, और गरीब लोगों को प्रत्यक्ष ही सामाजिक सेवा प्रदान करना।
- अधिकार दिलाना, जिसका अर्थ गरीब लोगों को सम्मिलित करना और उनकी हिस्सेदारी, सरकार को पारदर्शी और जवाबदार बनाना।
- सुरक्षा, अर्थात् गरीब लोगों द्वारा महसूस की जाने वाली जोखिमों, चाहे वह आर्थिक झटका हो, बीमारी हो, प्राकृतिक आपदा हो, या हिंसा आदि को कम करना।

समुदाय द्वारा प्रेरित विकास : इस अध्ययन द्वारा प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह थी कि गरीबी का अर्थ केवल आमदनी की कमी नहीं है। गरीबी का अर्थ है गरीबों के जीवन पर असर डालने वाले महत्वपूर्ण फैसलों पर कोई 'आवाज़' या राज्य या राष्ट्रीय स्तर की राजनैतिक संस्थाओं में अपने प्रतिनिधित्व का न होना है। इसके परिणामस्वरूप "समुदाय द्वारा प्रेरित विकास" जैसे कार्यक्रमों पर ध्यान अधिक केन्द्रित हुआ है जो समग्र समुदाय के धन और संसाधनों के राष्ट्रीय आवंटन पर अधिक अधिकार और नियंत्रण देता है और इस प्रकार भ्रष्टाचार से बचाता है और संस्थाओं के ही अन्दर अधिक शक्तिशाली "आवाज़" देता है। उदाहरण के लिये :

- एल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, और हांडुरज़ के ग्रामीण अँचलों में सामुदायिक शिक्षा समितियों को वित्तीय सहायता देना, जहाँ माँ-बाप स्कूल खर्च का प्रबन्ध स्वयं करते है, बच्चों की उपस्थिति आश्वस्त करते हैं, अध्यापकों को लाते हैं और उनके कार्यकौशल पर नज़र रखते हैं।
- लेटिन अमेरिका के चार शहरों, ग्वाटेमाला शहर, केराकस, साओ पॉलो, और रेसिफ में झोपड़ पट्टी हटाने का कार्यक्रम, जहाँ आसपास की संस्थाएं, जन समितियाँ, स्थानीय सरकार एवं निजी व्यवसाय, आवासीय सुधार और स्थानीय सेवाओं में सुधार ला कर बेहतर सामाजिक स्वास्थ्य और अपराध घटाने के लिये काम कर रही हैं।

सरकारी और निजी निवेश में बढ़ोत्री एवं विकास, जिसमें आधारभूत संरचना मे निवेश शामिल है। यह गरीबी कम करने के लिए जरूरी है।
सामान्यतया, आधुनिक और उन्नत संसाधनों तक पहुँच होने से स्वास्थ्य और शिक्षा के परिणामों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, पानी से फैलने वाली बीमारियों व श्वसन सम्बन्धी रोगों द्वारा होने वाली बच्चों की मृत्यु के दर में कमी होती है, तथा स्कूलों व दवाखानों तक पहुँच आसान हो जाती है।

विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ कार्य करने पर सफलता मिलती है :

- पेरू में, संसाधनों तक पहुँच के कारण घरेलू आय में उन लोगों की वृद्धि **45** प्रतिशत अधिक है अपेक्षा उनके जिनके पास ऐसी सेवायें नहीं है।
- निकारागुआ शहर में, उन इलाकों मे जहाँ गन्दे पानी के निकास की सुविधा में सुधार हुआ वहाँ बच्चों की मृत्यु दर **50** प्रतिशत घट गयी।
- मोरक्को में, पक्की सड़कों वाले स्थानों में, स्कूल में लड़कियों की उपस्थिति दुगुनी से भी अधिक हो गयी।

बैंक को उपलब्ध सीमित संसाधनों और आवश्यकताओं के विशाल स्तर को देखते हुये, सभी वित्तीय स्रोतों को प्रयोग में लाना एक चुनौती है। नीतियों मे सुधार पर ध्यान दे कर, क्षमता बढ़ा कर, और चुने हुए निवेशिक कार्यो का संचालन कर अन्य प्रकार के वित्तीय साधन जुटाने की सम्भावना बढ़ती है।

व्यापक विकास कार्ययोजना (काम्प्रिहेन्सिव डेवेलपमेन्ट फ्रेमवर्क या सी डी एफ)

विभिन्न देशों के बीच में चुनाव की प्रक्रिया प्रत्येक देश की विकास प्राथमिकता पर आधारित होती है। काम्प्रिहेन्सिव डेवेलपमेन्ट फ्रेमवर्क का विचार बैंक द्वारा कल्पित है और सभी परिचालनों में विकास संस्थाओं द्वारा अधिकतर अपनाया गया है।सी डी एफ के मूल सिद्वान्त किसी देश के अधिकार हैं, एक दीर्घकालिक और दूरदृष्टि की योजना है, हिस्सेदारों के बीच नीतिगत भागीदारी करना एवं विकास परिणामों के प्रति उत्तरदायी होने का ध्यान रखना है।

चाहे वह गरीब लोंगों पर कैसे खर्च करना हो, उन्हें विकास में हिस्सा लेने के लिये अधिकार देना हो, निवेश के लिये वातावरण बनाना हो, या फिर नौकरी व सतत गतिशील वृद्वि हो, सबसे वड़ी सफलता तभी सम्भव है जव कि विदेशी सहायता के सही ढंग से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं सहायता प्राप्त करने वाले देश लें। आज, ऋण प्राप्त कर्ता विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाते हैं, न कि बैंक। बैंक तो सिर्फ एक सलाहकार की भूमिका अदा करता है।

सी डी एफ प्रत्येक देश के विकास कार्यक्रम का मार्ग दर्शन, विकास के सभी मुद्दों - सामाजिक, ढाँचागत, मानवीय, शासकीय, पर्यावरणीय, आर्थिक और वित्तीय मुद्दों का ध्यान रखते हुए करता है। कार्यक्रमों में सभी के लिए वापस खरीदने का समान प्रावधान हो, जितना सामाजिक संस्थाओं व निजी क्षेत्रों को उतना ही सरकार और धनदाताओं को।

बैंक के लिये, सी डी एफ उन कार्यो को सक्रिय करता है जिन्हें अधिकतम प्रभाव हेतु चुना गया हो और जो देश सहायता संबंधी नीति के लिये आधार प्रदान करते हों। यह रणनीतियाँ, प्राय: तीन वर्ष तक के लिये होती हैं - जो प्रत्येक देश में बैंक के उधार और विना उधारी के कार्यक्रमों की रूपरेखा वताती है। गरीवतम देशों के मामले में, सी ए एस और सभी सहायताएं - जिनमें विकल्प होने पर ऋण मुक्ति भी, सम्मिलित है - अव प्राप्तकर्ता देशों द्वारा गरीवी कम करने की रणनीति पर लिखे जा रहे कच्चे मसौदे में शर्तो के अनुसार परिवर्तिन होगी, जो लम्वे समय तक प्रभावकारी, गरीवी पर केन्द्रित और सक्रिय साझेदारी वाला होगा।

क्षेत्रवार रणनीतियां

सहायता हेतु मार्गदर्शन का आधार मात्र किसी देश से देश तक लागू नहीं होता है बल्कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक लागू होता है। क्षेत्रीवार रणनीतियां बैंक की कार्य शैली और गतिविधियों को, किसी दिये विकासखण्ड या प्रासंगिक क्षेत्र में साकार करने में मदद करती हैं, देश की कमज़ोर कार्य कुशलता के मुद्दों को पहचान कर उन पर प्राथमिकता से ध्यान देती है। इसे प्रति तीन वर्ष में विस्तृत सलाह मशवरा के बाद संशोधित व पूर्ण किया जाता है, साथ ही साथ उन पर ऑनलाईन (इन्टरनेट द्वारा) पर भी चर्चा की जा सकती है।

शहरी यातायात इस वृत्त खण्ड की रणनीति की वर्तमान में समीक्षा की जा रही है।

बैंक ने अभी हाल में ही नये क्षेत्रों जैसे वन, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, लिंग, सूचना एवं संचार तकनीकों और निजी क्षेत्र के विकास पर रणनीतियां जारी की हैं।

अतिरिक्त क्षेत्रीय रणनीतियां निम्न विषयों पर उपलब्ध हैं :

भ्रष्टाचार-विरोधी

शिक्षा

शासन और सरकारी क्षेत्र में सुधार

स्वास्थ्य, पोषण और जनसंख्या (अफ्रीका के लिये एच आई वी/एड्स की रणनीति को भी देखें)

खनन (क्षेत्रीय रणनीति)

शहरी और स्थानीय सरकारें

जल संसाधनों का प्रवन्धन